

हीरे की परख करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच भी चमकने लगते हैं।

TODAY WEATHER



DAY

32°

Hi

NIGHT

28°

Low

संक्षेप

डीपफेक वीडियो के खिलाफ नितिन गडकरी की याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, एजेंसी। मुंबई, 28 जुलाई मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह एथॉल नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ अपलोड किए गए ‘‘अपमानजनक’’ ‘‘डीपफेक वीडियो’’ और कूत्रिम मेधा निर्मित पोस्ट के मामले में ‘भेदा’, ‘एक्स कोर्ष’, ‘गूगल एनएलसी’ और अज्ञात व्यक्तिों के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने केंद्रीय मंत्री के अधिवक्ता सदीप लड्डा को इस दावाानी याचिका की प्रतिया प्रतियादियों को सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में गडकरी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के प्रसार पर स्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। ‘डीपफेक’ वीडियो कूत्रिम मेधा (एआई) की मदद से इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसमें कोई व्यक्ति ऐसी बातें कहता या करता दिखाई देता है, जो उसने वास्तव में कभी नहीं कही। गडकरी ने अपनी याचिका में फर्जी और मनगढ़ंत सामग्री को तुरंत हटाने तथा ऐसी सामगियों के प्रसार पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि एथॉल-मिश्रित ईधन मुद्दे को लेकर इंटरनेट पर कई फर्जी, एआई-निर्मित और मानहानिकारक पोस्ट उपलब्ध हैं। याचिका में कहा गया है कि अज्ञात लोगों ने ‘डीपफेक वीडियो’ और पोस्ट अपलोड तथा प्रसारित किए हैं, जिनमें उन्हें एथॉल-मिश्रित ईधन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है और आरोप लगाया गया है कि इससे स्वयं केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार को वित्तीय लाभ हुआ है।

गृह मंत्री जवाब दें कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया : गौरव गोगोई

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की ‘‘विफलता का स्मारक’’ करार दिया और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। उन्होंने सदन में ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और यह दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून भी पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘‘मंत्री (जितेंद्र सिंह) के वक्तव्य और विधेयक के प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है और यह केवल दिखावे का विधेयक है।’’ उनके मुताबिक, 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमैड डॉ भी जमानत मिल गई।

# पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाबालिगों और बिना अपराधिक रिकॉर्ड वालों को रिहा करने के आदेश



**नई दिल्ली, एजेंसी।** नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही, पात्र छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

## क्या सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच के संकेत दिए?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छात्रों पर पुलिस की कथित ज्यादती के आरोप प्रथम दृष्टया निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। अदालत ने कहा कि पूरे मामले को पारदर्शी जांच के लिए आगे चलकर स्वतंत्र समिति या विशेष जांच दल (SIT) के गठन पर भी विचार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने उन सभी राज्यों को निर्देश दिया, जहां प्रदर्शन हुए थे, कि सीसीटीवी फुटेज, डोने रिकॉर्डिंग, बांडी कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पैसेीआर लॉग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक व

डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों से जुड़ा डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए।

## क्या सभी प्रदर्शनकारियों को राहत मिलेगी?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जबरन कार्रवाई से राहत केवल उन छात्र प्रदर्शनकारियों को मिलेगी, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर लागू नहीं होगी। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि सुनवाई पूरी होने तक पात्र छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

## राज्यों से भी मांगा गया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लागू गए आरोपों पर जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों के साथ-साथ प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के मामलों की

## लोकतंत्र में आंदोलन होते रहेंगे, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की जांच हो, जवाबदेही भी तय हो

देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के बारे में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि जवाबदेही तय करने के लिए स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का कहना है कि विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, और देश भर में सार्वजनिक प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों पर पुलिस की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। यह बात भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ इसलिए पुलिस की ज्यादतियों को सही नहीं ठहराया जा सकता कि कोई आंदोलन चल रहा है। बेंच ने रसंतुलितर रदैया अपनाने की बात कही और कहा कि असामाजिक तत्वों की हरकतों पर सजा मिलनी चाहिए। पिछले हफ्ते दिल्ली के जंतर-मंतर और कई अन्य शहरों में पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में रही है। दिल्ली में, प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किए जाने के बाद सुरक्षाकर्मी मुश्किल में पड़ गए हैं; इस कार्रवाई में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

## आप लोग गंदगी, बदसूरती और कचरा दिखा रहे जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर भड़कीं कंगना

फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों और Gen Z लोगों के व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने इन Gen Z प्रदर्शनकारियों की रील्स की भाषा, शैली और दृश्यों को ‘उट्टी लाने जैसा’, ‘अशिष्ट’ और ‘परेशान करने वाला’ करार दिया, साथ ही उन्होंने उनके सीडी तरीके के पालन-पोषण पर सवाल खड़े किए। साथ ही कंगना ने इन प्रदर्शनकारियों के व्यवहार की तुलना भारत की वास्तविक विरासत से भी की। उन्होंने भारत को ‘लालित्य से भरपूर और सांस्कृतिक परिवक्ता में रमा-बसा’ देश बताया। उन प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए जो मजाक या व्यंग्य में खुद को ‘कॉकरीच’ (कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की ओर इशारा) कहते हैं, वह कहती हैं कि वे वास्तव में उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हैं और दुनिया को अपनी ‘गंदगी, कचरा और बदसूरती’ दिखा रहे हैं। वह अंत में कहती हैं कि सोशल मीडिया पर आए इन वीडियोज को देखकर वह स्तब्ध हो गई और उन्हें इससे उबरने के लिए ‘डिजिटल डिटॉक्स’ यानी सोशल मीडिया से दूरी की जरूरत है।

भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है या अपनी सीमा से

# असम में बाढ़ का कहर जारी, पीएम मोदी ने कहा– पीड़ितों को बचाने केंद्र-राज्य सरकारें एकसाथ

**नई दिल्ली, एजेंसी।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मोदी ने संसद भवन परिसर में असम के केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों से मुलाकात के बाद यह बात कही। इस साल अब तक बाढ़ के कारण 68 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं।

बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाखरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मोर्गीटा ने भाग लिया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, बाढ़ से छह जिलों - शिवसागर, गोलाघाट,



चराइदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप (महानगर) में 4,45,495 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से कुल 90 राहत कैंप चल रहे हैं, जिनमें 28,695 लोगों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा, राहत सामग्री बांटने वाले 94 केंद्र भी काम कर रहे थे। बुलेटिन के अनुसार, NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस के जवानों समेत कई एजेंसियां बचाव और राहत का काम कर रही हैं और प्रभावित इलाकों में 67 नावें तैनात की गई हैं। ASDMA ने बताया कि 37,139.52 हेक्टेयर फसल वाला इलाका अभी भी पानी में डूबा हुआ है और 26,679

जानवर बह गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों के अलग-अलग हिस्सों से चरों, सड़कों और दूसरे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें मिली हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ; किसी नई मौत की खबर नहीं है और कई जिलों में पानी का स्तर घट रहा है। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय टीम ने मौजूदा बाढ़ की मार झेल रहे सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक, शिवसागर का दौरा किया और राज्य के पूर्वी हिस्सों में हालात का जायजा लिया।

# बलिया में जालसाजी के जरिये नौकरी हासिल करने के आरोप में सरकारी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

**बलिया।** जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी के जरिये नौकरी हासिल करने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, नवानगर शिक्षा क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर सोमवार की रात नगरा थाना में बेलसड़ी गांव के सरकारी कम्पोजिट विद्यालय के शिक्षक शिवनाथ यादव के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि शिवनाथ यादव छह दिसंबर, 1999 को शिक्षक के पद पर सेवायोजित हुआ था। भीमपुरा थाना क्षेत्र के खुंटा बहोतवां गांव के अजीत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिवनाथ यादव की नियुक्ति को लेकर शिकायत की थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इस शिकायत की जांच के बाद शिवनाथ यादव को 24 मार्च, 2026 को बर्खास्त कर दिया था। थाना प्रभारी संजय मिश्र ने बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

# मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों और ढाबों में मांसाहार पकाने और परोसने पर लगा प्रतिबंध

## आर्यावर्त क्रांति यूरो

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों और ढाबों में मांसाहार भोजन पकाने और परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही ढाबा मालिकों को प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करने तथा अपने नाम का विवरण प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुजफ्फरनगर (उप्र), 28 जुलाई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों और ढाबों में मांसाहार भोजन पकाने और



परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा, ‘‘यह व्यवस्था हर साल लागू रहती है।

कांवड़ यात्रा से पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले में श्रद्धालुओं के लिए विशुद्ध और सुरक्षित खाद्य

सुनिश्चित करने के लिए पूरे यात्रा मार्ग पर दुकानों, होटलों और ढाबों की जांच का अभियान चलाया है।’’ सहायक आयुक्त, खाद्य अर्चना धीरन ने मंगलवार को बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों और ढाबों में मांसाहार भोजन पकाने और परोसने पर प्रतिबंध

लगाया गया है और इन होटल और ढाबों को खाने में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि होटल और ढाबे हर साल इस नियम का पालन कर रहे हैं। नए होटल या ढाबों को विभाग द्वारा इस बारे में सूचना दी जाती है। खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए अधिकारियों की छह टीमें गठित की गई हैं। धीरन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए कदम उठाए गए हैं और खानपान की दुकानों को मालिकों का विवरण, लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा कनेक्ट ऐप क्यूआर कोड प्रदर्शित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों ने अधिक मूल्य वसूली रोकने के लिए 21 आवश्यक वस्तुओं की मानक दरें तय की हैं।

# प्रदेश में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, तरुण गाबा लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर

## आर्यावर्त क्रांति

**लखनऊ।** यूपी सरकार ने 15 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अशोक मुथा डीजी फायर सर्विस बनाए गए हैं। तबादला सूची के अनुसार, आईपीएस मधुर अशोक जैन को पुलिस महानिदेशक आनंशमन एवं आपात सेवाएं बनाया गया है। अमरेन्द्र कुमार सेंगर को पुलिस आयुक्त, लखनऊ से पुलिस महानिरीक्षक अभिरूचना मुख्यालय भेजा गया है, जबकि राम कुमार को लखनऊ रेंज से गोरखपुर जेन का अरु पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। नवीन अरोरा को तकनीकी



सेवाओं से वाराणसी जेन और पीयूष मोर्डिया को वाराणसी जेन से प्रयागराज पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में संजय गुप्ता को पुलिस मुख्यालय से एडीजी, कानून-व्यवस्था, तरुण गाबा को पुलिस आयुक्त, लखनऊ, और धर्मेन्द्र सिंह को प्रयागराज रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा मोहित गुप्ता, विनीत कुमार

सिंह, राजेंद्र कुमार, आनंद प्रकाश तिवारी, अरुण कुमार सिंह तथा आनंद कुमार सहित अन्य अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह तथा सुचारु बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नई तैनाती के बाद अधिकारियों से जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।





## तत्काल स्वास्थ्य लाभ के चक्कर में डॉक्टर शॉपिंग का नया चलन

समय के साथ सोच में एक बड़ा बदलाव तेजी से यह देखने में आ रहा है कि यदि जुखाम, बुखार, खांसी जैसी सामान्य बीमारी में भी डॉक्टर की दवा से तत्काल राहत नहीं मिलती तो अब डॉक्टर बदलने में कोई गुरेज नहीं होता। देखा जाए तो तुरंत स्वास्थ्य लाभ की प्रवृति के कारण डॉक्टर के इलाज पर विश्वास में कहीं ना कहीं कमी देखने में आने लगी है और इसके परिणाम स्वरुप महानगरों में डॉक्टर शॉपिंग का नया ही चलन चलने लगा है। खासतौर से मरीज से मिलने-मिलाने वाले चिकित्सक बदलने की सलाह देने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं करते। चिकित्सक बदलने में कोई बुराई नहीं है पर जिस चिकित्सक से इलाज करवा रहे हैं उससे बीमारी ठीक होने की संभावना के संबंध में चर्चा करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अन्य चिकित्सक की सलाह लेना और चिकित्सक बदलने में हमें अंतर करके चलना होगा। बीच ईलाज ही बार बार डाक्टर बदलने के कई साइड इफेक्ट से भी दो चार होना पड़ता है और कई बार तो डॉक्टर बदलने का यह प्रयोग ईलाज पर विपरीत प्रभाव और गंभीर संकट में डाल देता है। मिसाल के तौर पर सामान्य खांसी की बीमारी या पेट में गड़बड़ या वाइरल बुखार होने पर जब डॉक्टर द्वारा दवा का जो कोर्स दिया जाता है उसके पूरा होने के पहले ही यानी की मान लो पांच दिन का कोर्स दिया है तो तीसरे दिन ही अधीर होकर दूसरे डॉक्टर की शरण में जाना आम होता जा रहा है। हालांकि यह प्रवृति कुछ ही लोगों में है पर महानगरों और बड़े शहरों में इस तरह की प्रवृति जिस तेजी से बढ़ती जा रही है वह गंभीर चिंता का सबब बनती जा रही है। चिकित्सकीय भाषा में कहा जाए तो यह प्रवृति शॉपिंग का एक नया रुप डॉक्टर शॉपिंग के रुप में तेजी से फैलती जा रही है। हो यह रहा है कि इसके साइड इफेक्ट से अनजान होकर आगे बढ़ रहे है।

डॉक्टर शॉपिंग का कंसेप्ट बीसवीं सदी में नशीली दवाओं की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयासों के लिए चलन में आया था। नशीली दवाओं के आदतन लोग एक से दूसरे डॉक्टर के पास परचा लिखवाने इसलिए जाते थे ताकि नशीली दवाओं का संग्रह कर सके। क्योंकि नशीली दवा एक सीमा तक ही मिलती थी और बिना चिकित्सक के परचे के मिलना लगभग मुश्किल होता था। यही कारण है कि देश और विदेश में नित नए डॉक्टर से परचा लिखवाना और केमिस्ट से दवा प्राप्त करना आम होता जा रहा था। खासतौर से रोक वाली दवाओं को लेकर के यह प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। हालांकि इस प्रवृति को रोकने के लिए कई देशों में कानूनी प्रयास किये गए और कुछ हद तक इस पर अंकुश भी लग सका। अमेरिका जैसे देश में इसके लिए डॉक्टर शॉपिंग लॉ जैसी व्यवस्था की गई। खैर अब चिकित्सा सुविधा के विस्तार और सहजता के साथ ही डॉक्टर शॉपिंग का कंसेप्ट बदलता जा रहा है।

हो यह रहा है कि जब कोई मरीज यह महसूस करता है कि चिकित्सक की दवा से उसकी बीमारी में तेजी से सुधार नहीं हो रहा तो वह ईलाज के बीच ही दूसरे डॉक्टर की शरण में चले जाता है। खासतौर से यह प्रवृति महानगरों और बड़े शहरों में अधिक तेजी से फैल रही है। इसका कारण यह है कि आज सलाहकारों की लंबी फ़ौज होने के साथ ही रोगी या रोगी के परिजन मैजिक टच की सोच रखने लगे हैं। दूसरा यह कि अब चिकित्सा सुविधा का भी तेजी से विस्तार हुआ है। निजी और सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की सहज उपलब्धता होने के साथ ही मेडिकलेम जैसी सुविधाएं प्राप्त होने लगी है। सरकारी और निजी विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता के कारण भी यह होने लगा है। बीमारी चाहे सामान्य हो या गंभीर तत्काल सुधार नहीं दिखने पर दूसरे डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं और डाक्टर बदलने का तत्काल जो प्रभाव पड़ता है वह रीसेट बटन होता है यानी कि दूसरा डॉक्टर फिर अपने तरीके से पहले जाँचों का सिलसिला आरंभ करते हैं क्योंकि पहले की डॉक्टर द्वारा कराई गई जांचों में किसी ना किसी तरह की कमी या अन्य कारण बता कर दुबारा से जांचे करवानी पड़ती है। इसके लिए रक्त जांच से लेकर रोग के अनुसार एक्सरे, एमआरआई या अन्य तरह की जांचें भी हो सकती है। इससे बार बार जांच और एक्सरे किरणों से दो चार होने के साथ ही रुपये पैसे का भार भी पड़ता है। एक तरह से बीमारी के पहचान की नए सिरे से प्रक्रिया आरंभ होती है। दवा का नया सिलसिला आरंभ होता है और पूर्व में चल रही एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं के स्थान पर जेनेरिक दवाओं के ही दूसरे ब्राण्ड की दवा दी जाती है व कई बार तो पॉली फार्मसी जैसी स्थिति हो जाती है। दवाओं के असर पर विपरीत प्रभाव की संभावनाओं से भी नहीं नकारा जा सकता। ऐसे में सुधार के स्थान पर जटिलताओं की संभावनाओं से नहीं नकारा जा सकता। डॉक्टर शॉपिंग के इस दौर में अन्य चिकित्सक की विशेषज्ञ सलाह लेने और चिकित्सक बदलने में हमें अंतर करना होगा। अन्य विशेषज्ञ की सलाह को तो ईलाज कर रहे चिकित्सक को विश्वास में लेकर लेने से ईलाज में और अधिक सकारात्मकता आती है पर बार बार चिकित्सक बदलना उचित नहीं माना जा सकता।

### व्यंग्य

## अब युद्धस्तरीय तैयारी की आवश्यकता



हैकर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का अति संवेदनशील डेटा चुराने में सफल हो गए। संयंत्र में कंट्रोल, कूलिंग, और वेंटिलेशन के इंजीनियरिंग ब्लू प्रिंट; तथा विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं की सूची को डार्क वेब पर डाल दिया गया है।

डेटा चोरी की ताजा घटना ने भारत की साइबर सुरक्षा से संबंधित कमजोरियों को फिर उजागर किया है। न्यूक्लीयर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का दावा है कि लोक डेटा परमाणु सुरक्षा प्रणाली से संबंधित नहीं है। बहरहाल, इसे मान भी लिया जाए, तब भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हैकर भारतीय परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अति संवेदनशील डेटा चुराने में सफल हो गए। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में कंट्रोल, कूलिंग, और वेंटिलेशन के इंजीनियरिंग ब्लू प्रिंट; तथा विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं की सूची को 'वर्ल्ड लीक्स' नामक रैन्समवेयर ने चुरा लिया। इस डेटा के संचालन का ठेका 2018 में अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया था। इसके पहले 'वर्ल्ड लीक्स' ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से डेटा चुराकर उसे डार्क वेब पर डाल दिया था।

बताया जाता है कि दोनों घटनाओं को मिलकर लगभग 10 लाख से अधिक संवेदनशील फाइलें लोक हुई हैं। स्पष्टतः यह केवल दो निजी कंपनियों की सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है। बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भू-राजनीतिक साख, और वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पर सीधा प्रहार है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की मुख्य रिएक्टर प्रणाली भले सुरक्षित हो, लेकिन थर्ड पार्टी के सर्वर से संयंत्र की आंतरिक संवेदनशील संरचना का डार्क वेब पर पहुंच जाना दर्शाता है कि हमारी रणनीतिक सुरक्षा की कड़ुथि कितनी कमजोर है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित घटना भारतीय कॉरपोरेट जगत की आर्थिक और तकनीकी साख से संबंधित है।

ये कंपनी एप्ल, टेस्ला, और क्वालकॉम जैसी वैश्विक कंपनियों के व्यावसायिक डेटा को संभालती है। इनका 630 जीबी डेटा डार्क वेब के जरिए अब उनकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को उपलब्ध है। जाहिर है, इससे भारत की विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगा है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खास डेटा अगर सुरक्षित नहीं है, तो विदेशी निवेश लाने और तकनीकी हस्तांतरण की भारत की कोशिशों का सफल होना संदिग्ध बना रहेगा। इन घटनाओं ने साइबर कानूनों का सख्त अनुपालन कराने की भारत की क्षमता को कठघरे में ला खड़ा किया है। अतः सरकार और उद्योग जगत को इसे महज 'डेटा लीक' मानना बंद करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए अब युद्धस्तरीय तैयारी की आवश्यकता है।

## धर्मेंद्र प्रधान की सिर्फ मंत्री पद की कुर्सी गयी, राजनीतिक कद बरकरार है

| नीरज कुमार दुबे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>भारतीय राजनीति में संदेश अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि प्रतीकों से दिए जाते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में आज ऐसा ही एक प्रतीकात्मक दृश्य देखने को मिला। दो दिन पहले नीट पेपर लोक विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जब संसद पहुंचे तो बीजेपी और एनडीए सांसदों ने उनका स्वागत विजेता की तरह किया। र्धमैंद्र प्रधान जिंदाबादर के नारों से संसद परिसर गूंज उठा, पारंपरिक टोपी और शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया और मुस्कुराते हुए प्रधान ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया।</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>यहीं से सियासत का नया अध्याय शुरू हो गया। विपक्ष ने सवाल दगा कि क्या यह इस्तीफे का सम्मान था या जवाबदेही का मजाक? कांग्रेस ने इसे उस नेता का महिमामंडन बताया जिसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा से जुड़े कथित घोटाले के बाद पद छोड़ना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत समारोह पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने बिलकिस बानो मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह उसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है जिसमें विवादों से धिरे लोगों का भी सार्वजनिक सम्मान किया जाता है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा सांसद प्रधान का स्वागत ऐसे किया जा रहा है कि मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। उन्होंने आरोप लगाया कि देश ने पहले भी देखा है कि प्रधान ने अपने इस्तीफे में पेपर लोक के लिए माफी मांगने की बजाय छात्रों पर ही "गुमराह होने" का आरोप लगाया था। रमेश ने कहा कि इसके बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधान की “वाहवाही” की। कांग्रेस महासचिव ने कहा, “हमारा मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम अत्यंत शर्मनाक है और देश के युवाओं का घोर अपमान है।" हालाँकि बीजेपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान केवल पूर्व शिक्षा मंत्री नहीं हैं। वह पार्टी के सबसे भरोसेमंद संगठनकर्ताओं में गिने जाते हैं। ओडिशा के एक राजनीतिक परिवार में जन्मे प्रधान ने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। एबीवीपी के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता</div> |

| ब्लॉग |
|-------|
|       |

## ज्ञान, बुद्धि और विवेक : जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति

### ज्ञान की नदी, बुद्धि का प्रवाह और विवेक का सागर

| तेजबहादुर सिंह भुवाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| आज दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। विज्ञान, तकनीक और संचार के क्षेत्र में हो रहे तेज विकास ने मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। एक क्लिक पर अनगिनत जानकारीयें उपलब्ध हैं, लेकिन क्या केवल जानकारी का होना ही मनुष्य को महान बना देता है? इसका उत्तर स्पष्ट है—नहीं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए ज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का होना अनिवार्य है। यही तीनों गुण व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व और भविष्य की वास्तविक पहचान बनते हैं। |
| ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। यह हमें शिक्षा, अनुभव, अध्ययन, प्रकृति और समाज से प्राप्त होता है। ज्ञान मनुष्य को जागरूक बनाता है, उसकी सोच का विस्तार करता है और उसे नई संभावनाओं से परिचित कराता है। किंतु केवल ज्ञान अर्जित कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान व्यवहार में न उतरे, तो वह पुस्तकों के पन्नों तक ही सीमित रह जाता है।                                                                                            |
| ज्ञान को सार्थक बनाने का कार्य बुद्धि करती है। बुद्धि वह क्षमता है, जो सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं, जब व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उस समय केवल जानकारी नहीं, बल्कि सूझ-बूझ और दूरदर्शिता काम आती है। बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं से घबराता नहीं, बल्कि उनका समाधान खोजता है। वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना जानता है और असफलताओं को भी सीखने का अवसर बना लेता है।  |
| इन दोनों से भी श्रेष्ठ स्थान विवेक का है। विवेक वह आंतरिक चेतना है, जो हमें सही और गलत, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच अंतर करना सिखाती है। विवेक ही मनुष्य को नैतिक बनाता है। जब ज्ञान और बुद्धि के साथ विवेक जुड़ जाता है, तब व्यक्ति अपने निर्णय केवल स्वार्थ के आधार पर नहीं, बल्कि समाज और मानवता के हित को ध्यान में रखकर लेता है। यही गुण एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देता है।                                                          |

वर्तमान समय में ज्ञान का विस्फोट हुआ है, लेकिन विवेक का संकट भी उतना ही गहरा दिखाई देता है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने सूचनाओं का अंबर खड़ा कर दिया है। बिना सत्यापन के खबरें साझा करना, अफवाहों पर विश्वास करना और बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देना इस बात का संकेत है कि ज्ञान उपलब्ध है, पर विवेक का उपयोग कम हो



रहा है। इसलिए आज आवश्यकता केवल शिक्षित लोगों की नहीं, बल्कि विवेकशील नागरिकों की है। हमारे परिवार, विद्यालय और समाज की जिम्मेदारी है कि वे नई पीढ़ी को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि बहुमुख्य जीवन के लिए तैयार करें। बच्चों में पढ़ने की आदत, प्रश्न पूछने का साहस, तर्क करने की क्षमता और नैतिक मूल्यों का विकास ही उन्हें सच्चे अर्थों में शिक्षित बनाएगा। चरित्र के बिना ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है, जबकि विवेकयुक्त ज्ञान समाज के विकास का आधार बनता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महान व्यक्तियों की पहचान केवल उनके ज्ञान से नहीं, बल्कि उनके विवेकपूर्ण निर्णयों से बनी। उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। अतः हमें ज्ञान के अलावा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। ज्ञान हमें सीखने की प्रेरणा देता है, बुद्धि हमें सोचने की क्षमता प्रदान करती है और विवेक हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। यदि इन तीनों का संतुलित विकास हो जाए, तो व्यक्ति न केवल



युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायक, सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री बनने तक का उनका सफर संगठन की सीढ़ियां चढ़ते हुए तय हुआ। पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उज्ज्वला जैसी योजनाओं के विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही, जबकि 2021 में उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई।

ओडिशा में बीजेपी का संगठन खड़ा करने का श्रेय भी काफी हद तक धर्मेंद्र प्रधान को दिया जाता है। 2017 के पंचायत चुनावों से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2024 में बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत तक, उनकी रणनीति निर्णायक मानी जाती है। अमित शाह के करीबी राजनीतिक प्रबंधकों में उनकी गिनती होती रही है। पार्टी के भीतर उन्हें करिश्माई वक्ता से ज्यादा भरोसेमंद रणनीतिकार और संकटमोचक के रूप में देखा जाता है।

लेकिन शिक्षा मंत्रालय का कार्यकाल उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन अध्याय साबित हुआ। नई शिक्षा नीति, मातृभाषा आधारित शिक्षा और पीएम-श्री स्कूल जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के बावजूद उनका कार्यकाल लगातार विवादों में घिरा रहा। राष्ट्रीय परीक्षाओं में पेपर लोक के आरोप, एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के

आरोप, तमिलनाडु के साथ तीन-भाषा फार्मूले पर टकराव, 'हिंदी थोपने' के आरोप और शिक्षा संस्थानों के कथित भगवाकरण को लेकर विपक्ष के हमले लगातार उनका पीछा करते रहे। अंततः नीट विवाद वही मोड़ बन गया जिसने उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

देखा जाये तो संसद में धर्मेंद्र प्रधान को मिले सम्मान ने यह संकेत भी दे दिया कि भाजपा उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ने नहीं देना चाहती। माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही पार्टी संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव पद की जिम्मेदारी देने के अलावा उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया जा सकता है

बहरहाल, सभी को यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी शायद उन पुराने कॉलेजों की तरह नहीं है, जहां लकड़ी की बेंचों पर सिर्फ लोकप्रिय नारे लिखे मिलते हैं। उसकी राजनीतिक शिक्षा सत्ता के कठिन संघर्षों से हुई है, जहां आज से ज्यादा कल की चिंता होती है। शायद इसी वजह से पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अंत नहीं, बल्कि अगले अध्याय की शुरुआत की तरह पेश किया है। अब असली सवाल यह है कि क्या संसद में गूंजे धर्मेंद्र प्रधान रजिंदाबादर के नारे जनता के मन में उठे उन सवालों को भी दबा पाएंगे, जो लाखों छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़े हैं?





# आईटीआर फाइल करते समय बचाना चाहते हैं टैक्स, इन 6 जरूरी डिडक्शन को क्लेम करना न भूलें

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय अधिकतर लोग अपनी आय और टैक्स की जानकारी तो सही भर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे महत्वपूर्ण टैक्स डिडक्शन का दावा करना भूल जाते हैं, जिनकी मदद से उनकी टैक्स देनदारी काफी कम हो सकती है। इसका नतीजा यह होता है कि करदाता जरूरत से ज्यादा टैक्स चुका देते हैं। यदि आपने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करना है और पुराना टैक्स रिजीम चुना है, तो कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन का लाभ उठाकर अच्छी-खासी टैक्स बचत की जा सकती है।

ध्यान रखने वाली बात यह है कि नए टैक्स रिजीम में इन अधिकांश डिडक्शन का लाभ उपलब्ध नहीं होता। इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले दोनों टैक्स रिजीम की तुलना जरूर कर लें, ताकि यह तय किया जा सके कि किस विकल्प में आपको अधिक बचत मिलेगी।

अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), टैक्स सैविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, इंग्लएसएस, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन बीमा प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस या होम लोन के मूलधन का भुगतान किया है, तो सेक्शन 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। यह टैक्स बचाने का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रावधान है।

वहीं, अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश किया है, तो सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है। यह छूट सेक्शन 80सी से अलग होती है। यानी 80सी और 80सीसीडी(1बी) को मिलाकर कुल 2 लाख रुपए तक की टैक्स बचत संभव है।

यदि आपने अपने, जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। यह छूट परिवार की स्थिति और वरिष्ठ नागरिकों के आधार पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि, प्रीमियम का भुगतान बैंकिंग माध्यम से किया गया होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा के लिए लिया गया एजुकेशन लोन भी टैक्स बचाने में मदद करता है। सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन



एनुअल चुकाए गए ब्याज की पूरी राशि पर निर्धारित अवधि तक टैक्स छूट मिलती है। इसमें किसी अधिकतम सीमा का प्रावधान नहीं है। हालांकि, यह छूट केवल ब्याज पर मिलती है, लोन के मूलधन पर नहीं।

वहीं, अगर आपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था, ट्रस्ट या राहत कोष में दान दिया है, तो सेक्शन 80जी के तहत 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत तक टैक्स छूट मिल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दान किस संस्था को दिया गया है। डिडक्शन का दावा करने के लिए दान की रसीद और संबंधित संस्था का पंजीकरण विवरण सुरक्षित रखना जरूरी है।

इसके साथ ही, अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है तो सेक्शन 24(बी) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह छूट केवल ब्याज पर मिलती है, जबकि होम लोन का मूलधन सेक्शन 80सी के तहत क्लेम किया जाता है।

रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 16,

इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और फॉर्म 26एएस का मिलान जरूर कर लें, ताकि आपकी आय और टैक्स कटौती की जानकारी में कोई अंतर न रहे। जिन डिडक्शन का दावा करना है, उनसे जुड़े सभी दस्तावेज और रसीदें अपने पास रखें। साथ ही, अपनी आय और निवेश के अनुसार सही टैक्स रिजीम का चयन करें। बैंक खाते, पैन, आधार और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सही दर्ज करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आईटीआर दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर पूरा करें, क्योंकि इसके बिना आपकी रिटर्न प्रक्रिया अधूरी मानी जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर रिटर्न भरना केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सही टैक्स प्लानिंग का भी हिस्सा है। यदि आप उपलब्ध टैक्स डिडक्शन का सही तरीके से लाभ उठाते हैं और सभी जरूरी दस्तावेजों का मिलान करके रिटर्न दाखिल करते हैं, तो न केवल अतिरिक्त टैक्स देने से बच सकते हैं बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की टैक्स संबंधी परेशानी से भी दूर रह सकते हैं।

# एनवीडिया, ओपनएआई के मेगा डेटा सेंटर के लिए 250 अरब डॉलर की वित्तीय गारंटी देने के लिए कर रही बातचीत : रिपोर्ट

अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, यूएस में बनने वाले ओपनएआई के विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए करीब 250 अरब डॉलर की वित्तीय गारंटी उपलब्ध कराने पर बातचीत कर रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित वित्तीय समर्थन से चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई को दक्षिणी ओहायो में सॉफ्टबैंक की ऊर्जा इकाई द्वारा विकसित किए जा रहे 10 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर परिसर को लीज पर लेने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परियोजना की कुल लागत 500 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है, जिसमें इस डेटा सेंटर को संचालित करने वाले एनवीडिया के एआई चिप्स की लागत भी शामिल है।

प्रस्तावित 250 अरब डॉलर की गारंटी डेटा सेंटर की लीज और डेट फाइनेंसिंग को कवर करेगी, लेकिन इसमें चिप्स की लागत शामिल नहीं होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया ओपनएआई द्वारा 350 अरब डॉलर तक के एआई चिप्स की खरीद के लिए फाइनेंसिंग पर भी चर्चा कर रही है।

ओपनएआई के लिए यह समझौता अपनी खुद का एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक

बड़ा कदम होगा। इससे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और ओरेकल जैसे क्लाउड सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता कम कर सकेगी।

वहीं, एनवीडिया के लिए यह व्यवस्था उसके एआई चिप्स की दीर्घकालिक मांग सुनिश्चित करने में मददगार होगी। इन चिप्स का उपयोग उन्नत एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और संचालित करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह वित्तीय सहायता उन निवेश ढांचों को भी मजबूत करेगी, जिनका उद्देश्य इस परियोजना के फंडिंग को लेकर ऋणदाताओं का भरोसा बढ़ाना है।

ओहायो में बनने वाली इस परियोजना का पहला चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 800 मेगावाट बिजली क्षमता उपलब्ध होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस परियोजना के लिए बिजली आपूर्ति का नियंत्रण अमेरिकी सरकार के पास होगा और इसकी फंडिंग जापान करेगा। यह हाल ही में हुए व्यापार समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत दोनो देशों ने 33 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस संयंत्र में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के बड़े औद्योगिक समूहों और एनवीडिया सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने करीब 950 अरब डॉलर मूल्य की कई सहयोगी

परियोजनाओं की संभावनाओं पर सहमति जताई थी। यह जानकारी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई थी।

प्रस्तावित पहलों में एक दीर्घकालिक समझौता भी शामिल है, जिसके तहत उसके ग्रुप (एसके ग्रुप) वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, जिनमें एनवीडिया भी शामिल है, को लगभग 750 अरब डॉलर मूल्य के उच्च-प्रदर्शन सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराएगा। यह जानकारी राष्ट्रपति के नीति मामलों के प्रमुख सचिव किम योंग-वोम ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी।

यह सहमति सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में बनी, जिसमें वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों और दक्षिण कोरिया के प्रमुख कारोबारी समूहों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष ली जे-योंग और एसके ग्रुप के चेयरमैन चे ताए-वोन शामिल थे।

बैठक में ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम आल्टमैन और एनवीडिया के संस्थापक एवं सीईओ जेनसन हुआंग भी मौजूद रहे। उनकी भागीदारी अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने के लिए एआई डेवलपर्स और सेमीकंडक्टर कंपनियों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती है।



# कोई मुझे न बताए हमें क्या बेचना है और क्या नहीं... नेतन्याहू की आपत्ति पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप

**वॉशिंगटन, एप्रैल 11।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेबाकी और बेअंदाजी के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं। ट्रंप ने कल सोमवार को तुर्की को अमेरिकी F-35 फाइटर जेट बेचने के मामले में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी नेता अमेरिका की हथियारों की बिक्री पर असर नहीं डालता है। साथ ही यह भी कहा कि कोई मुझे यह नहीं बताए कि हमें क्या बेचना चाहिए और क्या नहीं।

‘एयर फोर्स वन’ में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की को हथियार दिए जाने पर इजराइली पीएम नेतन्याहू की चिंताओं को खारिज किया और तुर्की को एक



अमेरिका का “बेहतरीन सहयोगी” करार दिया। ट्रंप ने कहा, “कोई मुझे यह नहीं बताए कि हमें क्या बेचना चाहिए। तुर्की मेरे लिए हमेशा से एक बेहतरीन सहयोगी रहा है।”

राष्ट्रपति ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई है, जब नेतन्याहू कल सोमवार को ट्रंप के साथ हाई लेवल स्तरीय बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुंचे। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत

में क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान के साथ जारी संघर्ष मुख्य एजेंडा शामिल रहेगा। अखबार CNN की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में पीएम नेतन्याहू ने तुर्की को अमेरिकी

F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की संभावना का कड़ा विरोध जताया था। यही नहीं उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि ऐसा कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल देगा।

CNN को दिए इंटरव्यू में पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने निजी तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप से इस बिक्री को अपनी मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया है क्योंकि अमेरिका की ओर से यह संकेत दिया गया कि वह अपने पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा, “अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट के खरीदने मात्र से तुर्की अमेरिका का मित्र देश नहीं हो जाएगा।”

**व्यों डील का विरोध कर रहे**

**PM नेतन्याहू**

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अंकारा एक ऐसी सरकार है जो ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ से प्रभावित है और अमेरिका से नफरत भी करती है। इजराइली पीएम ने कहा, “वह अमेरिका का आदर्श सहयोगी भी नहीं है।”

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, “वह मेरे देश, यानी एकमात्र यहूदी देश को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है।” नेतन्याहू ने आगाह भी किया कि तुर्की को ये विमान देने से इलाके में बड़े नतीजे सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप से गुजारिश की है कि वे तुर्की को फाइटर जेट न

बेचें, क्योंकि ऐसा करने से “मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन बिगड़ जाएगा।”

**तुर्की हमारे लिए कहीं अधिक वफादार : ट्रंप**

अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह बात तब सामने आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन जल्द ही तय करेगा कि फाइटर जेट बेचे जाएं या नहीं। साथ ही, उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अंकारा की ओर से रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।

तुर्की को फाइटर जेट दिए जाने को लेकर ट्रंप ने कहा, “तुर्की के साथ हमारे संबंध बेहतर रहे हैं, और तुर्की कई मामलों में उन देशों की तुलना में

कहीं अधिक वफादार रहा है जिनके बारे में हमें लगता था कि वे वफादार होंगे।” उन्होंने यह तर्क भी दिया कि कई लोगों का मानना ​​है कि रूसी S-400 सिस्टम खरीदने के बावजूद तुर्की को F-35 खरीदने की इजाजत दी जानी चाहिए।

F-35 जेट को “अब तक का सबसे बेहतरीन जेट” करार देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि प्रस्तावित बिक्री “निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिस पर हम विचार करेंगे।” CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संकेत दिया कि अंकारा को लगता है कि वह अमेरिकी F-35 फाइटर जेट और तुर्की के अपने KAAAN फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिकी इंजन खरीदने की डील के करीब है।

# नीरव मोदी को अब तक भारत की जेल में होना चाहिए था अपने ही देश के सिस्टम पर भड़कीं यूके की पूर्व गृह मंत्री, उठाए ये सवाल

**ब्रिटेन।** भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में हो रही देरी को लेकर ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपनी ही सरकार और कानूनी प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में देरी होने की वजह से भारत और ब्रिटेन के के रिश्तों पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी देरी से भारत के साथ भरोसा कम हुआ है। ‘द डेली टेलीग्राफ’ के पॉडकास्ट ड डायमंड किंग में बातचीत के दौरान प्रीति पटेल ने कहा कि उन्हें यह देखकर हैरानी और निराशा होती है कि प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के सालों बाद भी नीरव मोदी अब तक ब्रिटेन में मौजूद है।



प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में भगोड़े हीरा व्यापारी के प्रत्यर्पण नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले ब्रिटेन की अदालतों ने माना था कि भारत में उसके खिलाफ मुकदमा

चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। अप्रैल ने कहा कि उन्हें इस बात से बहुत हैरानी और दुख है कि मोदी अभी भी UK में ही है।

**ब्रिटेन के सिस्टम पर उठाए सवाल**

उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में कथित तौर पर 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वॉट्स कारोबारी को प्रत्यर्पित न कर पाने के कारण भारत सरकार बेहद नाराज

थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारा सिस्टम प्रक्रियाओं और बहानेबाजी में उलझे रहने की बजाय समझदारी से काम करता और सही कदम उठाता तो मोदी इस देश में नहीं होता और वो अब तक भारत भेजा जा चुका होता। उन्होंने आगे कहा कि इस देरी की वजह से भारत को हमारे साथ काम करने को लेकर काफी निराशा हुई है।

**‘अब तक भारत की जेल में होता नीरव’**

प्रीति पटेल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीरव मोदी को अब तक भारत में अपनी सजा काटनी शुरू कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा ‘उसे भारत की जेल में अपनी सजा काटनी चाहिए थी, और यह सब कानूनी प्रक्रिया के तहत

होना चाहिए था, यही तो UK के प्रत्यर्पण कानूनों और संधियों का मकसद है’। उन्होंने इस लंबी देरी को ब्रिटेन के सिस्टम का खुला दुरुपयोग और ब्रिटिश टैक्सपेयर्स का अपमान बताया।

**भारत-ब्रिटेन संबंधों पर भी पड़ा असर**

उन्होंने दावा किया कि 2019 से 2022 के बीच उनके होम सेक्रेटरी रहने के दौरान इस मामले ने डिप्लोमैटिक चुनौतियां भी खड़ी कीं। उन्होंने बताया कि जब तक प्रत्यर्पण का मामला सुलझ नहीं, तब तक भारत उन लोगों को वापस लेने में सहयोग करने को तैयार नहीं था जिनकी शरण की अर्जी नामंजूर हो गई थी। उन्होंने कहा ‘भारत को शरण की अर्जी नामंजूर होने वाले

लोगों को वापस लेने के लिए राजी करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और मेरा मानना ​​है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे पास (नीरव मोदी का) यह हाई-प्रोफाइल मामला था और उस समय एक और हाई-प्रोफाइल मामला भी था।जब तक उन्होंने (भारत ने) उन मामलों में कोई कार्रवाई या प्रगति नहीं देखी, तब तक उनके पास हमारे ऊपर दबाव बनाने का एक ज़रिया था, जो बहुत निराशाजनक था’।

**नीरव की उसकी आखिरी अपील भी खारिज**

नीरव मोदी ने UK में अपने सभी कानूनी विकल्प आजमा लिए हैं और खबर है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स में उसकी आखिरी अपील भी खारिज हो गई

है। मानवाधिकारों के आधार पर अपील और शरण के गोपनीय दावे समेत कई सालों की कानूनी चुनौतियों के बाद अब उनके भारत प्रत्यर्पण को लगभग तय माना जा रहा है।

**लंदन की पेंटनविल जेल में बंद है नीरव**

55 वर्षीय नीरव मोदी फिलहाल लंदन की पेंटनविल जेल में बंद है। भारत में उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब 2 अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी का सीबीआई मामला, प्रवर्तन निदेशालय (ED) का मनी लॉन्ड्रिंग मामला और सर्वोत्त एंव गवाहों से छेड़छाड़ से जुड़ा मामला शामिल है।



# रक्षा, परमाणु और AI... भारत-अमेरिका में बड़ी डील, इकॉनमी को मिलेगा तगड़ा बूस्ट



**नई दिल्ली, एजेंसी।** अमेरिकी विदेश उप-सचिव एस पॉल कपूर ने कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और ज्यादा काम करेंगे। दोनों देश मिलकर सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऐसी नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कपूर ने ये बातें हूवर इंस्टीट्यूशन में भारत पर आयोजित एक राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस में कहीं।

इस बैठक में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री कौडेलीजा राइस और भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत डेविड सी मुलफोर्ड भी शामिल थे। पॉल कपूर ने दबीट कर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत होने से भारत में रोजगार (नौकरियां) बढ़ रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच सामानों की सप्लाई चेन बेहतर हो रही है, जो भारत, अमेरिका और इस पूरे इलाके के लिए बहुत फायदेमंद है।

**‘रक्षा, परमाणु और AI में बढ़ाएंगे सहयोग’**

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दोनों देश मिलकर रक्षा, परमाणु ऊर्जा और भरोसेमंद AI जैसी नई तकनीकों पर काम बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। बता दें कि पिछले साल दोनों देशों ने

# प्रभास की स्पिरिट में कैटरीना कैफ की एंट्री? 2 साल बाद एक्ट्रेस की बड़े पर्दे पर होगी वापसी?



साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ महीने पहले ही दीपिका पादुकोण इस फिल्म से बाहर हो चुकी हैं, जिसके बाद फिल्म में तृप्ति डिमरी और प्रभास की जोड़ी देखने को मिलेगी। इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी फिल्म का हिस्सा बनने वाली हैं, जो फैंस के बीच चर्चा में है।

रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के मेकर्स कैटरीना कैफ से कैमियो के लिए बात कर रहे हैं। फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, लेकिन वो एक मजबूत किरदार में दिखाई देंगी। अगर कैटरीना फिल्म में नजर आती हैं, तो ये उनके फैंस के लिए बहुत खास होने वाला है। शादी के बाद बड़े पर्दे पर वो बहुत कम दिखाई दी हैं और कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाईं। इसीलिए स्पिरिट उनकी बड़ी फिल्मों में से एक हो सकती है। हालांकि कैटरीना या मेकर्स ने इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पहले दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आने वाली थीं। लेकिन न्यूज़ 18 शोशा के अनुसार, उन्होंने मेकर्स से 8 घंटे की शिफ्ट, 25 करोड़ फीस के अलावा फिल्म के प्रॉफिट का 10% की मांग की थी। इसी वजह से मेकर्स और उनके बीच बात नहीं बनी और उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया। इसके बाद तृप्ति डिमरी को फिल्म के लिए चुना गया और वो दीपिका से कम फीस ले रही हैं।

वहीं बात करें कैटरीना की, तो उन्होंने करीब 20 साल पहले मल्लिकार्जुन में वेंकटेश और अल्लारी पिडुगु में नंदामुरी बालकृष्ण के साथ तेलुगु फिल्म में काम किया था। बाद में वो बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय रही और आखिरी बार उन्हें 2024 में मेरी क्रिसमस फिल्म में विजय सेतुपति के साथ देखा गया।

# पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, गाइडलाइंस तय करने की मांग

**नई दिल्ली, एजेंसी।** दिल्ली के जंतर-मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में नीट पेपर लोक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें न सिर्फ प्रदर्शनकारी बल्कि कई पुलिसकर्मियों भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। वहीं अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

जानकारी के मुताबिक घायल हुए पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में इयूटी के दौरान हिंसा का सामना करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा और स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है। यह याचिका ACP कैलाश सिंह बिष्ट, ASI संदीप, कांस्टेबल धीरज और ASI हेमन्धर राठी के परिजनों की तरफ से दायर की गई है। ये सभी सभी जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इयूटी पर घायल हो गए थे।

याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि पुलिसकर्मियों को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का समान संरक्षण मिले और पुलिस के खिलाफ हिंसा भड़काने या उकसाने वाले लोगों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इयूटी पर तैनात पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट गाइडलाइन बनाई जाए।

**‘अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जरूरी’**

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिसकर्मियों अक्सर हिंसा का सामना करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश जरूरी हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इयूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

**सुप्रीम कोर्ट पुलिस कार्रवाई पर कर रहा सुनवाई**

यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट

# बॉक्स ऑफिस पर गद्दा कुश्ती 2 बनीं ऐश्वर्या लक्ष्मी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर, एक और बनाया रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस पर अक्सर छोटे बजट की फिल्में धाकड़ कलेक्शन करती हैं। बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्मों का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में तमिल की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म गद्दा कुश्ती 2 ने शानदार बिजनेस कर लिया है। फिल्म रिलीज होते ही छा गई थी। इसमें कोई बड़ी स्टारकास्ट नहीं है। अब फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए बताते हैं इसके बारे में।

फिल्म गद्दा कुश्ती 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने के लिए मिला। ऐश्वर्या लक्ष्मी की इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में एंट्री कर चुकी है। फिल्म चौथे हफ्ते भी अच्छी खासी कमाई कर रही है और रिपोर्ट के अनुसार, इसका नेट कलेक्शन 40 करोड़ के पार हो गया है और फिल्म मामन को इसे पछाड़ दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, गद्दा कुश्ती 2 ने 16 दिनों के बाद फिल्म का नेट कलेक्शन 40 169 करोड़ हो चुका है। इसने ऐश्वर्या लक्ष्मी की 2025 में आई फिल्म मामन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसका लाइफटाइम नेट कलेक्शन 40 120 करोड़ था।

गौरतलब है कि गद्दा कुश्ती 2 की कमाई में थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज के बाद ब्रेक लग गया है। जन नायकन रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया है। इसने तमिल ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों की भी छुट्टी कर दिया है।

बहरहाल, अगर फिल्म के प्रॉफिट की बात की जाए तो गद्दा कुश्ती 2 का नेट कलेक्शन 40 169 करोड़ हो चुका है और कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी बजट 27 करोड़ है। इस लिहाज से फिल्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है। फिल्म ने 50 170% प्रॉफिट कमा लिया है।

इसके अलावा अगर फिल्म गद्दा कुश्ती 2 के बारे में बात की जाए तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा तमिल फिल्म है। इसका निर्देशन निर्देशन चेल्ला अय्यावु ने किया है। फिल्म में ऐश्वर्या लक्ष्मी के साथ ही एक्टर विष्णु विशाल ने लीड रोल प्ले किया है।

# डी55 के शीर्षक से उठा पर्दा, धनुष और राजकुमार पेरियासामी की फिल्म ओम : चैप्टर 1 से पोस्टर भी जारी

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले धनुष की डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी के साथ 55वीं फिल्म का ऑफिशियल टाइटल तमिल में ओम: चैप्टर 1 और तेलुगु में ओम: फर्स्ट स्ट्राइक रखा गया है। आर टेक स्टूडियोज और वंडरबार फिल्म्स मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और यह उनका पहला साथ में किया गया प्रोजेक्ट है। हाल ही में कास्ट, क्यू और मीडिया की मौजूदगी में इसका टाइटल लॉन्च किया गया।

अमरन की पैन-ड्रॉइया सफलता के बाद, राजकुमार पेरियासामी इस बड़े बजट वाले एक्शन ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है। टीम ने कन्फर्म किया है कि सिनेमेटोग्राफर एंजिलारसु, अमरन और करप्पु के एडिटर कलाईवानन और म्यूजिक कंपोजर साई अर्थ्यकर टेक्निकल क्यू का हिस्सा हैं।

मेकर्स ने पोस्टर के बजाय एक खास वीडियो के जरिए धनुष के किरदार को दिखाते हुए ओम का खुलासा किया। डायरेक्टर राजकुमार ने कहा कि इस टाइटल के स्प्रिचुअलिटी

(आध्यात्मिकता) से परे कई गहरे मतलब हैं। फिल्म के रिलीज होने से पहले आने वाले महीनों में लीड किरदारों के टीजर और ट्रेलर जारी किए जाएंगे।

ओम में धनुष, साई पल्लवी, श्रीलीला और मलयलम सुपरस्टार मम्मी (एक अहम रोल में) जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं। इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह तमिल सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। वंडरबार और आर टेक स्टूडियो को फिल्म के बड़े स्कैल और कहानी पर बहुत भरोसा है।

डिवो म्यूजिक और वार्नर म्यूजिक इंडिया इसके ऑडियो का काम संभालेंगे। अमरन के साथ राजकुमार की सफलता को देखते हुए, इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ओम: चैप्टर 1 को 16 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और यह पहले से ही उस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है।

